रणजीत टाइम्स

इंदौर

बुधवार, 18 मार्च, 2026

वर्ष 02 | अंक 71 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

सहज स्वभाव

सहज स्वभाव में स्थित व्यक्ति सदैव विजयी होता है : श्री माताजी

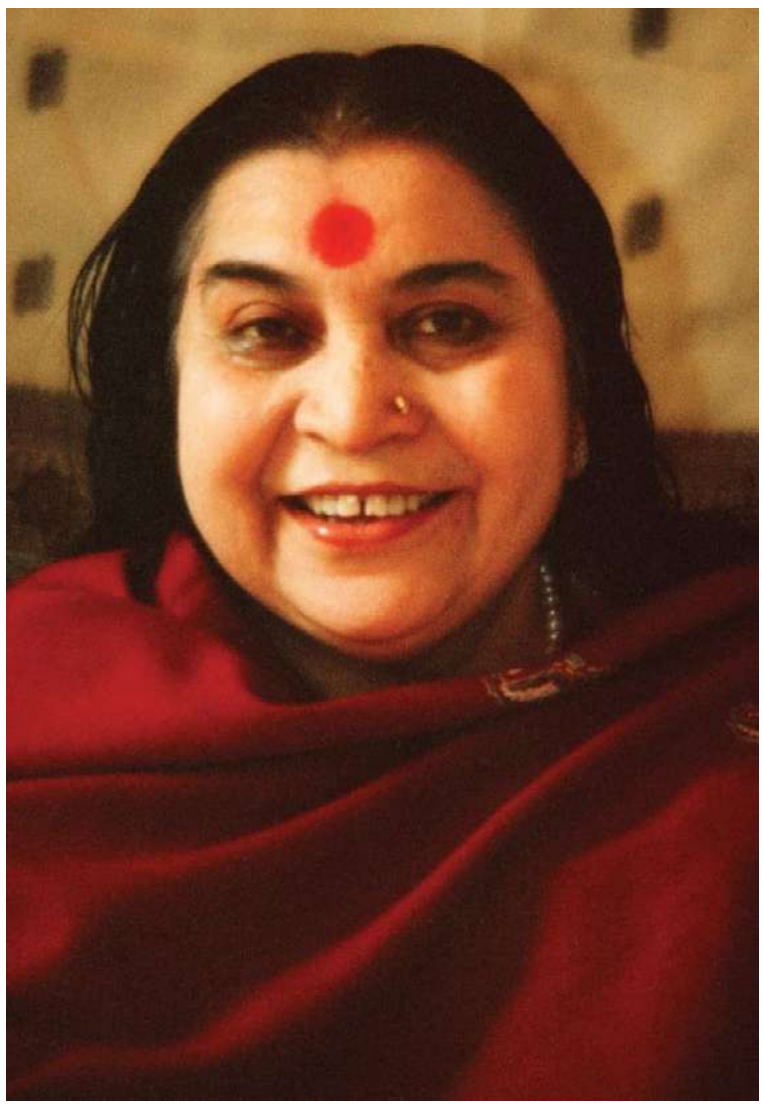

सहजयोग श्री माताजी निर्मला देवी जी द्वारा प्रतिस्थापित एक जीवंत वैज्ञानिक पद्धति है। सहजयोग कोई यौगिक अथवा शारीरिक क्रिया नहीं है वरन् सहजता से जीवन को जीना है। सहज रूप से जब हमारा योग अर्थात् जुड़ना परम शक्ति से हो जाता है तब हम सहजयोगी हो जाते हैं। सहजयोग कोई नई विचारधारा, संप्रदाय अथवा धर्म नहीं है यह तो संपूर्ण सृष्टि को चलायमान रखने वाला परमात्मा का यंत्र है। मनुष्य को परमशक्ति द्वारा बुद्धि प्रदान कर विचारों की स्वतंत्रता प्रदान की गई और इसी बुद्धि ने उसे असहज बना दिया। मानव जाति को इस भटकाव से बचाने के लिए अनेक अवतार, गुरु, व संत इस संसार में समय समय पर परमात्मा की इच्छा से अवतरित हुए और सभी ने सहजता की ही बात की व सहज जीवन को ही जिया। भारत में अनेकानेक ऐसे संत हुए हैं जो अपने गुणों के द्वारा देव तुल्य हो गए। ऐसे ही संत कबीर दास जी का नाम संतों की अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। जीवन की सहजता का वर्णन संत कबीर दास जी ने अपने दोहे में इस प्रकार किया है कि, सहज सहज सब कोई कहै,सहज न चीन्हें कोय |

जिन सहजै विषया तजै, सहज कहावै सोय ||

अर्थात् सहज - सहज सब कहते हैं, परन्तु उसे समझते नहीं जिन्होंने सहजरूप से विषय - वासनाओं का परित्याग कर दिया है, उनकी निर्विषय-स्थिति ही सहज कहलाती है। कबीर दास जी द्वारा वर्णित इसी सहजता की प्राप्ति सहजयोग में श्री माताजी के सानिध्य व कृपा में आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति के पश्चात् होती है। हम अपने सहज स्वभाव में स्थित रहने लगते हैं व समस्त दुश्चिंताओं से शारीरिक कष्टों से मुक्ति संभव हो जाती है। इस का वर्णन करते हुए श्री माताजी ने कहा है कि, "जब आप भगवान के साम्राज्य में खड़े होते हैं खुशी के साम्राज्य में तो हर हाल में तुम राजा और रानी बनते हो। कोई भी आपको खरीद नहीं सकता या आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आप सब कुछ जीत लेते हैं।" सहजयोग ध्यान का आनंद और अनगिनत लाभ लेने हेतु अपने नज़दीकी सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 से प्राप्त कर सकते हैं।

गैस सिलेंडर वितरण में अनियमितता का आरोप

सिमलिया की जनता में रोष

सिमलिया क्षेत्र की इंडियन गैस एजेंसी पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सिलेंडर वितरण प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिससे आम उपभोक्ता परेशान हैं और जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है।

क्या है पूरा मामला?

स्थानीय निवासियों के अनुसार, सिलेंडर बुकिंग के बावजूद समय पर डिलीवरी नहीं हो रही। उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिससे रसोई का काम प्रभावित होता है। वहीं आरोप है कि कुछ खास लोगों को बिना प्रतीक्षा के सिलेंडर उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिससे वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

DBC कनेक्शन धारकों के साथ सबसे बड़ा अन्याय

डबल बॉटल कनेक्शन (DBC) धारकों की स्थिति और भी गंभीर बताई जा रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि पहला सिलेंडर 21 दिन बाद भी नहीं मिलता, जबकि दूसरे सिलेंडर के लिए 45 दिन तक इंतजार कराया जाता है। जबकि DBC का उद्देश्य ही निरंतर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था इसके विपरीत दिखाई दे रही है। KYC के नाम पर उत्पीड़न एजेंसी पर यह भी आरोप है कि KYC अपडेट न होने का हवाला देकर सिलेंडर देने से मना किया जा रहा है।

जबकि नियमों के अनुसार

e-KYC घर बैठे मोबाइल ऐप और Aadhaar FaceRD के माध्यम से किया जा सकता है। केवल 9 महीने से निष्क्रिय कनेक्शन पर KYC अनिवार्य है। e-KYC न होने पर भी 7वें रिफिल तक सब्सिडी जारी रहती है। इसके बावजूद नियमित उपभोक्ताओं को एजेंसी के चक्कर लगाने पर मजबूर किया जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से नियमों के विपरीत है। नियमों का उल्लंघन तेल कंपनियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार DBC उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराना डीलर की जिम्मेदारी है। 45 दिन की देरी उपभोक्ता अधिकारों का सीधा हनन है।

प्रशासन से कार्रवाई की माँग आक्रोशित नागरिकों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से मांग की है कि: DBC उपभोक्ताओं को हो रही देरी की जांच की जाए KYC के नाम पर हो रहे उत्पीड़न पर रोक लगे घर बैठे e-KYC की सुविधा सुनिश्चित की जाए दोषी डीलर पर लाइसेंस निरस्तीकरण सहित सख्त कार्रवाई हो

अधिकारी मौन क्यों?

इस मामले में संबंधित अधिकारियों से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। प्रशासन की चुप्पी से जनता का संदेह और बढ़ गया है।

जब एक उपभोक्ता को पहले सिलेंडर के लिए 21 दिन और दूसरे के लिए 45 दिन इंतजार करना पड़े, और KYC के नाम पर परेशान किया जाए, तो यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित उत्पीड़न का संकेत है।

काबुल में बिछी लाशें, पाकिस्तान की बमबारी में 400 लोगों की मौत, शवों को निकालने का काम जारी

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग अब अधिक भीषण हो गई है। इसी बीच पाकिस्तान ने भीषण हवाई हमला कर दिया है और काबुल में अस्पताल में भारी बमबारी की है, जिसमें 400 लोगों की मौत हो गई है और 250 से अधिक घायल हो गए है। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इमरजेंसी टीमें रात भर मौके पर पहुंचीं, जब बचाव दल हॉस्पिटल के खराब हिस्सों में तलाशी ले रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफ जमान ने कहा कि कम से कम 170 घायल मरीजों को शुरू में पास की मेडिकल सुविधाओं में भेजा गया। तालिबान की सरकार के अधिकारियों के अनुसार, यह हमला रात करीब 9 बजे काबुल में 2,000 बेड वाले उम्मीद नशा मुक्ति हॉस्पिटल को निशाना बनाकर किया गया। तालिबान के उपप्रवक्ता मुल्ला हमदुल्ला फितरत ने कहा कि हमले से पूरे हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा तबाही हुई है।

3 साल से चल रहा वेतन विवाद खत्म

आंतरी स्लीपर फैक्ट्री में समझौते से लौटी कामकाज की रफ्तार

कालीचरण

आंतरी क्षेत्र की स्लीपर फैक्ट्री में लंबे समय से फैक्ट्री प्रबंधन और श्रमिकों के बीच चल रहा वेतन विसंगति का विवाद आखिरकार सुलझ गया। यह मामला पिछले कई वर्षों से श्रमिकों और मालिक पक्ष के बीच तनाव का कारण बना हुआ था, जिसके चलते कामकाज भी प्रभावित हो रहा था और श्रमिकों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा था। जिला रिपोर्टर कालीचरण की पहल पर दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। इस दौरान श्रमिकों ने अपनी वेतन संबंधी परेशानियों, काम के घंटे और अन्य सुविधाओं से जुड़ी मांगों को विस्तार से रखा, वहीं फैक्ट्री मालिक ने भी अपनी व्यावसायिक चुनौतियों और परिस्थितियों को सामने रखा। बातचीत का यह दौर काफी समय तक चला, जिसमें दोनों पक्षों को समझाने और संतुलन बनाने का प्रयास किया गया।

अंततः आपसी सहमति के आधार पर एक सकारात्मक समाधान निकलकर सामने आया। फैक्ट्री मालिक श्री हरीश भोजवानी और श्रमिकों के बीच तीन वर्षों के लिए एक सहमति पत्र यानी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस अनुबंध के तहत वेतन विसंगतियों को दूर करने और भविष्य में किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए स्पष्ट शर्तें तय की गई हैं। इस समझौते से लंबे समय से चला आ रहा विवाद पूरी तरह समाप्त हो गया और फैक्ट्री में सामान्य स्थिति बहाल हो गई है।

समझौते के बाद श्रमिकों के चेहरे पर संतोष नजर आया और उन्होंने इस पहल की सराहना की। इस अवसर पर श्री राजवीर सिंह गुर्जर, श्री मनोज किरार सहित सभी श्रमिकों ने आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है, जिससे अब वे पूरी निष्ठा के साथ अपने काम पर ध्यान दे सकेंगे। इस समझौते को क्षेत्र में एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, जहां संवाद और आपसी समझ के जरिए एक जटिल विवाद को सुलझाया गया। इससे न केवल श्रमिकों और प्रबंधन के बीच विश्वास मजबूत हुआ है, बल्कि औद्योगिक माहौल भी बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है।

दिल्ली में 20 साल में हार्ट अटैक ने ली इतने लाखों लोगों की जान, इसमें 14, 000 बच्चे भी हैं शामिल

दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश की राजधानी में में 2024 में दिल का दौरा और दिल से संबंधित बीमारियों के कारण 34,539 मौतें हुईं, जो पिछले साल की तुलना में 12,000 से ज़्यादा मौतें हैं जब 22,385 मौतें दर्ज की गई थीं। इसमें यह भी पता चला कि पिछले दो दशकों में दिल्ली में 3,29,857 मौतें दिल के दौरे के कारण हुईं। दर्ज की गई कुल मौतों में से पांच प्रतिशत से अधिक (14,321) मौतें 14 वर्ष और उससे कम उम्र के लोगों की थीं।

25 से 44 वर्ष के लोग हो रहे ज्यादा शिकार

दिल्ली सरकार की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 25 से 44 वर्ष की आयु वर्ग में 46,129 मौतें दर्ज की गईं, जबकि 45 से 64 वर्ष की आयु वर्ग में 1,03,972 लोगों की मौत दिल के दौरे से हुई और 65 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में 92,048 लोगों की मौत हुई। बीएम बिड़ला हार्ट हॉस्पिटल की बाल हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. मधुरिमा घोष ने कहा- "हालांकि वंशानुगत जोखिम महत्वपूर्ण बना हुआ है, लेकिन जीवनशैली कारक अब शुरुआती दिल के दौरे में एक बड़ी और अधिक बदली जा सकने वाली भूमिका निभाते हैं। आनुवंशिकी बंदूक लोड कर सकती है, लेकिन जीवनशैली ट्रिगर खींचती है। खराब आहार, निष्क्रियता, धूम्रपान, तनाव और नींद की कमी बहुत कम उम्र में आनुवंशिक प्रवृत्ति को सक्रिय कर सकती है।"

महिलाओं के मुकबाले पुरुष हो रहे हार्ट अटैक का ज्यादा शिकार

2005 और 2024 के बीच, दिल से संबंधित समस्याओं के कारण हुई कुल मौतों में से 2,10,206 पुरुष, 1,19,626 महिलाएं और 25 अन्य थे। अधिकतम 34,539 मौतें 2024 में दर्ज की गईं और न्यूनतम 8,236 मौतें 2010 में दर्ज की गईं। आंकड़ों के आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि 45-64 वर्ष की आयु वर्ग में, दिल का दौरा/बीमारियों के कारण पुरुष मौतों की संख्या महिला मौतों की संख्या से लगभग दोगुनी थी। कुल 68,177 पुरुषों और 35,795 महिलाओं की मौतें दर्ज की गईं। "आज के समय में, शुरुआती हार्ट अटैक में आनुवंशिक जोखिम की तुलना में लाइफस्टाइल फैक्टर ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि जेनेटिक्स भी जोखिम बढ़ा सकते हैं, लेकिन खराब आदतें ही इसके मुख्य कारण हैं।

इन कारणों से आता है हार्ट अटैक

कुछ फैक्टर जैसे कि सुस्त दिनचर्या, ज़्यादा स्क्रीन टाइम, खाने की खराब आदतें, धूम्रपान, वेपिंग, खराब नींद और ज़्यादा तनाव का स्तर जीवन में बहुत पहले ही दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाता है" । हार्ट अटैक और संबंधित बीमारियों के कारण होने वाली संस्थागत मौतें 45-64 साल के आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा थीं (38.55 प्रतिशत), इसके बाद 65 साल और उससे ज़्यादा आयु वर्ग।

11.4 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला: पांच राज्यों के नोडल अधिकारियों, फर्जी संस्थानों और छात्रों पर CBI की एफआईआर

सीबीआई ने दिव्यांग छात्रों के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति निधि से 11.4 करोड़ रुपये से अधिक के गबन मामले में पांच राज्यों के नोडल अधिकारियों, फर्जी संस्थानों और छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह मामला अंब्रेला छात्रवृत्ति योजना से जुड़ा है। यह योजना 2018 में दिव्यांग छात्रों के लिए शुरू की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि जिन राज्यों के अज्ञात लोक सेवकों और नोडल अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है, उसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। अंब्रेला छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के साथ-साथ मैट्रिक के बाद के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के छात्रों को भी छात्रवृत्ति मिलती थी। यूजीसी/एआईसीटीई की ओर से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री और डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा के छात्रों को भी इन छात्रवृत्तियों के अंतर्गत वित्त पोषित किया जाता था। आरोप है कि 28 संस्थानों से जुड़े ऐसे 926 छात्रों को 11.41 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई, जो या तो फर्जी थे या मंत्रालय के निरीक्षण के दौरान उनमें गंभीर अनियमितताओं का पता चला था। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के सचिव की शिकायत पर प्रारंभिक जांच शुरू की थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि इनमें से कई संस्थान अस्तित्वहीन थे या बंद हो चुके थे, फिर भी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से धनराशि का दावा कर रहे थे। एजेंसी ने पाया कि जम्मू और कश्मीर स्थित सत्यम कॉलेज ऑफ एजुकेशन 2017 से बंद था। फिर भी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर फर्जी यूजर आईडी बनाकर इसके छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति के दावे किए जा रहे थे। इस साजिश में कई स्कूलों का नाम उनकी जानकारी के बिना इस्तेमाल किया जा रहा था। सीबीआई ने बताया कि राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्यों के 11 संस्थानों ने बताया कि उन्हें इस योजना की जानकारी नहीं थी।

रणजीत टाइम्स

इंदौर : रहवासियों के भारी विरोध के आगे झुका मकान मालिक, एयरटेल (Indus) टावर हटाने के लिए लिखा पत्र

दीपक वाड़ेकर

इंदौर। शहर की सिल्वर पार्क कॉलोनी (फेस-1) में घर की छत पर मोबाइल टावर लगाने को लेकर उपजा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। रहवासियों के कड़े विरोध और एकजुटता के बाद अंततः मकान मालिक रामबाबू कटारिया ने बैकफुट पर आते हुए संबंधित कंपनी (Airtel-Indus) को टावर हटाने के लिए लिखित आवेदन दे दिया है।

क्या है पूरा मामला?

सिल्वर पार्क कॉलोनी के मकान नंबर 299 पर बिना किसी वैध एनओसी (NOC) के मोबाइल टावर खड़ा कर दिया गया था। जैसे ही रहवासियों को इसकी भनक लगी, उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी खतरों और रेडिएशन का हवाला देते हुए मोर्चा खोल दिया। रहवासियों का आरोप है कि यह टावर न तो ग्राम पंचायत से स्वीकृत है और न ही रहवासी संघ से इसके लिए कोई अनुमति ली गई है।

मकान मालिक ने दी 'नुकसान' की चेतावनी

भारी विरोध प्रदर्शन के बीच मकान मालिक रामबाबू कटारिया ने इंडस टावर के मैनेजर को पत्र लिखकर कहा है कि-"कॉलोनीवासियों के विरोध और रेडिएशन के डर के कारण मैं अब इस टावर को लगवाने के पक्ष में नहीं हूँ। इसे तुरंत हटाया

जाए। यदि भविष्य में टावर या उसके सामान को कोई नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी।"

सरपंच की भूमिका पर उठे सवाल इस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय सरपंच सत्यनारायण बोड़ाना की भूमिका को लेकर भी रहवासियों में काफी आक्रोश देखा गया।

अनुपस्थितिः रहवासियों का कहना है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें कई बार फोन किया गया और मौके पर बुलाया गया, लेकिन वे नहीं आए।

सरपंच का पक्षः जब पत्रकार ने सरपंच से इस बारे में बात की, तो उन्होंने 'व्यस्तता' का बहाना बनाया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत द्वारा टावर के लिए कोई एनओसी जारी नहीं की गई है।

नोटिस का ड्रामाः सरपंच ने दावा किया कि उन्होंने मकान मालिक को नोटिस जारी किया था, लेकिन "गलत नंबर" डल जाने के कारण वह रिसीव नहीं हुआ और अब दोबारा भेजा गया है।

रहवासी संघ ने दी चेतावनी

सिल्वर पार्क रहवासी रखरखाव संस्था के अध्यक्ष कैलाश बाथम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षरित आवेदन जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को सौंपे हैं। रहवासियों का

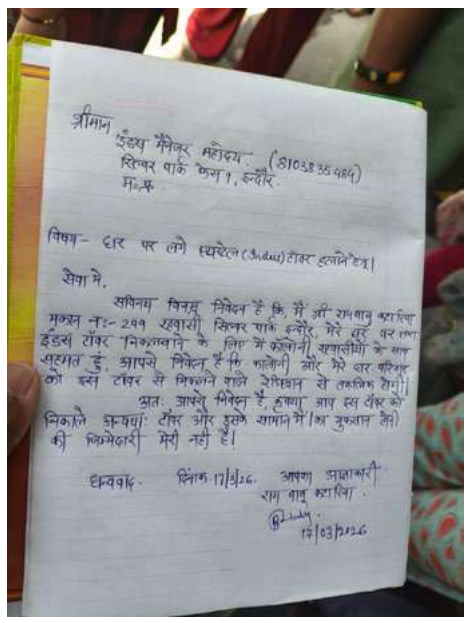

साफ कहना है कि रिहायशी इलाके में इस तरह के व्यावसायिक और रेडिएशन वाले टावर किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

करारी हार के बाद बिहार 'महागठबंधन' में दरार!

राज्यसभा चुनाव में सभी पांच सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने जीत हासिल की। मतदान के दौरान विपक्षी 'महागठबंधन' के चार विधायकों की गैरहाजिरी से राजनीतिक समीकरण बदल गया। इससे NDA को निर्णायक बढ़त मिल गई। कांग्रेस के तीन विधायकों और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के एक विधायक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। राज्यसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब RJD के कार्यकर्ता कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। RJD के आम कार्यकर्ताओं में भारी आशंकाएं पैदा हो गई हैं। वे अब इस हार के लिए कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं।

बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर

राज्यसभा चुनाव के बहाने बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। चुनावी गणित जहां महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं, मतदान के दिन चार विधायकों की गैरहाजिरी ने पूरा समीकरण बदल दिया। नतीजतन NDA ने पांचों सीटों पर जीत हासिल की और महागठबंधन की रणनीति विफल हो गई।इस चुनाव में पांचवीं सीट सबसे अधिक चर्चा में रही, क्योंकि यहां मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा था। इस सीट को जीतने के लिए NDA को तीन अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की आवश्यकता थी। जबकि महागठबंधन को छह विधायकों के वोट की जरूरत थी।

तेजस्वी यादव की कोशिश नाकाम

महागठबंधन की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संख्या जुटाने के लिए रणनीति बनाई थी। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के पांच विधायकों तथा मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी (BSP) के एक विधायक का समर्थन भी हासिल कर लिया था। संख्याबल के इस समीकरण के बाद महागठबंधन को भरोसा था कि पांचवीं सीट उसके खाते में जाएगी। लेकिन मतदान के समय उसके चार विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे। फिर यहीं से पूरा समीकरण बदल गया। मतदान से अनुपस्थित रहने वालों में कांग्रेस के तीन विधायक वाल्मीकिनगर से सुरेंद्र कुशवाहा, फारबिसगंज से मनोज विश्वास और मनिहारी से मनोहर सिंह शामिल हैं।

शराब ठेका निष्पादन में फेल, जिलों पर शासन की नजर, नोकरशाहो की कुर्सी खतरे में!

आबकारी में डबल चार्ज और ठेका निष्पादन में कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों की गोपनीय समीक्षा, प्रशासनिक सर्जरी की आहट

भोपाल। प्रदेश में शराब दुकानों के ठेका निष्पादन की प्रक्रिया के बीच अचानक एक नई हलचल ने आबकारी विभाग और प्रशासनिक गलियारों में सस्पेंस पैदा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, जिन जिलों में ठेका निष्पादन अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया या जहां बार-बार प्रक्रिया विफल होती रही, उन जिलों को अब शासन ने गंभीरता से चिन्हित कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस विषय पर की गई शिकायत (हमारे द्वारा) के बाद शासन स्तर पर पूरी स्थिति की गोपनीय समीक्षा शुरू हो गई है। खासकर वे जिले जहां अधिकारी एक साथ दो-दो जिलों का प्रभार यानी डबल चार्ज संभाल रहे हैं, वहां की प्रशासनिक स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। साथ ही बड़े संभागीय जिले भी निशाने पर है! सूत्रों की मानें तो ठेका निष्पादन जैसे महत्वपूर्ण और राजस्व से जुड़े कार्य के दौरान कई जिलों में नेतृत्व की कमी साफ दिखाई दी। कुछ स्थानों पर निर्णय लेने में देरी हुई तो कहीं प्रक्रिया बार-बार अटकती रही। ऐसे में अब शासन जवाबदेही तय करने के मूड में दिखाई दे रहा है।

अंदरखाने चर्चा यह भी है कि जिन जिलों में प्रदर्शन कमजोर रहा है, वहां जल्द ही प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि शासन ऐसे अधिकारियों को हटाने या उनके स्थान पर नए अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार कर रहा है... हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन विभागीय हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि "फाइलें चल चुकी हैं" और कुछ जिलों में अफसरों की कुर्सियां हिलना लगभग तय माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह समीक्षा केवल चेतावनी बनकर रह जाएगी या फिर वाकई कुछ जिलों में प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिलेगी।

इंदौर में 'बस्ती बेमिसाल' अभियान की शुरुआत, 29 स्लम बस्तियों में चलेगा स्वच्छता अभियान

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शिवनगर से किया शुभारंभ, श्रमदान कर दिया स्वच्छता का संदेश

इंदौर। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से इंदौर नगर निगम द्वारा 'बस्ती बेमिसाल' अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 17 से 23 मार्च तक शहर की 29 स्लम बस्तियों में संचालित किया जाएगा। अभियान का शुभारंभ वार्ड क्रमांक 31 स्थित शिवनगर बस्ती में महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान आयोजित स्वच्छ चौपाल में जनप्रतिनिधियों ने रहवासियों से कचरा संग्रहण, गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण तथा आसपास की स्वच्छता बनाए रखने को लेकर संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान महापौर, आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने स्वयं श्रमदान कर सफाई कार्य में भाग लिया और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया। इस मौके पर क्षेत्रीय पार्षद बाल मुकुंद सोनी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर की स्वच्छता में बड़ी कॉलोनियों के साथ-साथ स्लम बस्तियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और क्षेत्रों को रेड स्पॉट मुक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी बताया कि स्वच्छ और सुंदर बस्ती के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वहीं निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने नागरिकों से अपील की कि वे नगर निगम के साथ मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं। अभियान के तहत 18 से 22 मार्च तक विभिन्न बस्तियों में सौंदर्यीकरण, पौधारोपण और स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जबकि 23 मार्च को स्लम कार्निवाल का आयोजन होगा। इसके साथ ही स्वच्छता चौपाल, पेंटिंग प्रतियोगिता और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। महापौर ने कहा कि इंदौर की स्वच्छता में स्लम बस्तियों का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम सभी को मिलकर अपने क्षेत्रों को साफ-सुथरा रखना होगा और रेड स्पॉट मुक्त बनाना होगा। '

इंदौर में 'ओपन स्पेस टैक्स' पर सियासत तेज, विपक्ष ने वसूली रोकने की मांग

कांग्रेस का निगम कार्यालय पर प्रदर्शन, टैक्स को बताया मनमाना और जनविरोधी

इंदौर। शहर में 'ओपन स्पेस टैक्स' (MOS) को लेकर सियासत गरमा गई है। इंदौर नगर निगम द्वारा मकानों और भवनों के खुले हिस्से (मार्जिन/ओपन स्पेस) पर लगाए गए टैक्स का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को निगम कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने मांग की है कि ओपन स्पेस टैक्स की वसूली तत्काल प्रभाव से रोकी जाए। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने इसे 'मनमाना और जनविरोधी' करार देते हुए कहा कि इस टैक्स से आम नागरिकों पर भारी आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के अधिकांश मकानों में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा ओपन स्पेस (MOS) के रूप में होता है, जिस पर टैक्स लगाकर पिछले पांच वर्षों का बकाया एक साथ वसूला जा रहा है, जो न्यायसंगत नहीं है। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस नेत्री सोनिला मीमरोड, राजेश चौकसे, दीपू यादव, विनय बाकलीवाल, संजय बाकलीवाल, राजू भदौरिया सहित कई पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चिंटू चौकसे ने चेतावनी दी कि यदि टैक्स पर रोक नहीं लगाई गई, तो कांग्रेस आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि ओपन स्पेस टैक्स पूरी तरह से जनविरोधी है। इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। निगम आयुक्त, क्षितिज सिंघल, ने कहा कि नगर निगम द्वारा नियमों के तहत ही टैक्स लगाया गया है। नागरिकों की आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है।

बेरिकैड तोड़ने वाले चालक पर केस

इंदौर। चैकिंग के दौरान एक शराबी वाहन चालक ने पुलिस के बेरिकैड तोड़ दिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। लसूड़िया पुलिस के अनुसार घटना सत्यसाई चौराह गुजराती स्कूल के पास हुई। आरोपी वाहन चालक का नाम ध्रुव अग्रवाल पिता विपिन अग्रवाल निवासी सांघी स्ट्रीट महू है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई तो वह शराब पीया पाया गया।

इंदौर में बिना फायर एनओसी चल रहे अस्पताल, कटक जैसी घटना का खतरा

- दर्जनभर बड़े अस्पतालों के पास नहीं है फायर एनओसी, कलेक्टर ने एडीएम को सौंपी जांच

इंदौर। उड़ीसा के कटक में सरकारी मेडिकल अस्पताल में आग लगने से हुई मौतों की घटना के बाद इंदौर में भी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर में लगभग 100 बेड या उससे अधिक क्षमता वाले कई अस्पताल ऐसे हैं, जिनके पास फायर एनओसी नहीं है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन्हें संचालन की अनुमति दे दी गई है, जो एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित एसएनएस हॉस्पिटल, आर्थोस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिस्टा हॉस्पिटल, लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल, मयूर हॉस्पिटल, प्रमिला हॉस्पिटल, आरएन कपूर मेमोरियल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, सेवाकुंज हॉस्पिटल, शुभदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और इंदौर सिटी हॉस्पिटल सहित कई संस्थानों के पास फायर एनओसी नहीं है। जानकारी के अनुसार शहर में करीब तीन दर्जन बड़े अस्पताल हैं, जिनमें से दर्जनभर इस अनिवार्य सुरक्षा अनुमति के बिना संचालित हो रहे हैं। इस संबंध में अधिवक्ता चर्चित शास्त्री ने कलेक्टर को शिकायत करते हुए मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और यह जांच सीएमएचओ डॉ. माधव हासानी से न कराकर किसी अन्य सक्षम अधिकारी से कराई जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि कटक जैसी घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इंदौर में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए अस्पतालों में फायर एनओसी की जांच कराई जाएगी।

इंदौर में ट्रांसजेंडर समुदाय का विरोध, एक्ट में बदलाव रोकने की मांग

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कहा—प्रस्तावित संशोधन से 50% ट्रांसजेंडरों पर पड़ेगा असर

इंदौर। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ इंदौर में ट्रांसजेंडर समुदाय ने विरोध जताया। बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और एक्ट में किसी भी तरह के संशोधन पर रोक लगाने की अपील की। समुदाय के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस एक्ट में बदलाव का सीधा असर ट्रांसजेंडर समुदाय के लगभग 50 प्रतिशत लोगों पर पड़ेगा। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो हिजड़ा कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि अपने परिवार के साथ रहते हैं, शिक्षित हैं और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं। ट्रांसजेंडरों ने बताया कि वर्ष 2019 में लागू इस एक्ट के माध्यम से उन्हें कई महत्वपूर्ण अधिकार मिले थे, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। ऐसे में प्रस्तावित संशोधन उनके अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इस एक्ट में बदलाव नहीं करने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से मौजूदा प्रावधानों को यथावत बनाए रखने की अपील की। इस दौरान ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि निकुल जैन सहित अन्य सदस्यों ने अपनी बात रखी, वहीं कलेक्टर कार्यालय की ओर से ज्ञापन लेकर उचित स्तर पर भेजने का आश्वासन दिया गया।

नो एंट्री विवाद पर मंडी में हड़ताल: व्यापारियों के बंद से किसान परेशान, नीलामी ठप

बिना सूचना बंद से भड़के किसान, मंडी परिसर में नारेबाजी; प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

इंदौर। छावनी अनाज मंडी में मंगलवार सुबह उस समय हालात बिगड़ गए, जब नो एंट्री व्यवस्था से नाराज व्यापारियों ने अचानक हड़ताल का ऐलान कर दिया। बिना पूर्व सूचना के दुकानें बंद होने से मंडी में नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई। हड़ताल की जानकारी न होने के कारण बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच गए। मौके पर पहुंचने के बाद जब उन्हें व्यापारियों की हड़ताल की जानकारी मिली तो किसानों में आक्रोश फैल गया। नाराज किसानों ने मंडी परिसर में एकत्र होकर व्यापारियों और मंडी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि यदि हड़ताल करनी थी तो इसकी सूचना पहले दी जानी चाहिए थी, ताकि वे अपनी फसल लेकर मंडी न आते। कई किसानों ने बताया कि वे दूर-दराज के गांवों से किराए के वाहनों में उपज लेकर पहुंचे हैं और अब एक दिन रुकना उनके लिए आर्थिक रूप से नुकसानदायक है। मंडी के बाहर किसानों के वाहनों की लंबी कतार लगने से यातायात भी प्रभावित हुआ। वहीं, कुछ दुकानों के शटर खुले होने के बावजूद व्यापारी नीलामी में शामिल नहीं हुए और कामकाज ठप रहा। किसानों ने मांग की कि हड़ताल तत्काल समाप्त कर नीलामी और तुलाई शुरू की जाए। साथ ही मंडी प्रशासन से हस्तक्षेप कर नो एंट्री की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की अपील की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे मामले को भोपाल स्तर तक उठाएंगे। फिलहाल, मंडी प्रशासन और व्यापारियों के बीच बातचीत जारी है और समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इंदौर का खेल दिल फिर जख्मी है... और इस बार भी निशाने पर वही पुराना नाम—नेहरू स्टेडियम

फिर उजड़ा मैदान, फिर टूटा खिलाड़ियों का सपना

इंदौर। शहर के खिलाड़ियों की आखिरी उम्मीदों में शामिल नेहरू स्टेडियम एक बार फिर बदहाली का शिकार हो गया है। खेल के नाम पर आयोजित बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट ने इस ऐतिहासिक मैदान की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि अब यहां खेलना तो दूर, चलना भी मुश्किल हो गया है। मैदान के बीचों-बीच टावर खड़े करने के लिए गहरे गड्ढे खोद दिए गए, और अब चारों तरफ बड़े-बड़े पत्थर और बोल्डर फैले पड़े हैं। जिस मैदान पर रोज हजारों बच्चे अपने सपनों को आकार देने आते थे, आज वही मैदान खतरनाक और ऊबड़-खाबड़ नजर आ रहा है।

खेल के नाम पर खिलवाड़- सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक नेहरू स्टेडियम को 'इवेंट ग्राउंड' बनाकर उसकी आत्मा को कुचला जाता रहेगा? कभी चुनावी रैली, कभी राजनीतिक सभा, तो कभी भव्य आयोजनों के नाम पर यह मैदान बार-बार बर्बाद किया जा रहा है। खेल सुविधाओं की कमी से जूझ रहे इंदौर में जहां पहले ही मैदानों की संख्या लगातार घट रही है, वहीं जो गिने-चुने मैदान बचे हैं, उनकी यह हालत प्रशासन की प्राथमिकताओं पर बड़ा सवाल खड़ा करती है।

खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़- स्थानीय खिलाड़ियों और कोचों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक मैदान की बर्बादी नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 'हम रोज यहां प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अब यहां पैर रखना भी मुश्किल है,' एक युवा खिलाड़ी ने नाराजगी जताते हुए कहा-

जिम्मेदार कौन?

आखिर इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

क्या आयोजकों पर कोई कार्रवाई होगी?

क्या मैदान को जल्द से जल्द खेलने लायक बनाया जाएगा?

या फिर हर बार की तरह यह मुद्दा भी कुछ दिनों की नाराजगी के बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा?

अब नहीं तो कब?

इंदौर जैसे खेलप्रेमी शहर में यदि खिलाड़ियों को सुरक्षित और बेहतर मैदान नहीं मिलेंगे, तो फिर 'खेलो इंडिया' जैसे अभियानों का क्या मतलब रह जाएगा?

इंदौर में जमीन कब्जे को लेकर विरोध: साहू समाज ने कलेक्टर कार्यालय घेरा, कार्रवाई की मांग तेज

इंदौर। शहर में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को साहू समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एक गरीब परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। जानकारी के अनुसार, राजेश साहू, जो लोडिंग रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं, ने करीब 20 वर्ष पहले किस्तों पर 400 वर्गफीट का प्लॉट खरीदा था। आरोप है कि उसी प्लॉट पर सचिन शुक्ला नामक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया और पीड़ित को लगातार परेशान किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वे कई बार थाने के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पूर्व में एसडीएम से भी शिकायत की गई थी, जहां उन्हें थाने जाने की सलाह दी गई, लेकिन वहां भी कोई समाधान नहीं मिला। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति पूर्व पार्षद रह चुका है और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पीड़ित को धमका रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक पीड़ित को उसकी जमीन वापस नहीं मिलती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। मामला छोटा बांगर्डा स्थित श्रीनाथ विहार क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

2 मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख, हज यात्रियों के लिए अनिवार्य जांच व टीकाकरण

इंदौर। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2026 पर जाने वाले यात्रियों के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और अनिवार्य टीकाकरण को लेकर सर्कुलर जारी किया है। जारी निर्देशों के अनुसार सभी हज यात्रियों को निर्धारित समयसीमा के तहत अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि यात्रियों को अपने मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र अंतिम तिथि तक जमा करना होगा, क्योंकि इसके बाद ही वीजा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समय पर सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर वीजा प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। निर्देशों के मुताबिक सऊदी अरब का हज और उमरा मंत्रालय द्वारा तय स्वास्थ्य मानकों का पालन सभी यात्रियों के लिए जरूरी होगा। इसमें भारत के साथ-साथ एनआरआई हज यात्री भी शामिल हैं। हज कमेटी ने यह भी बताया कि आवश्यक टीकाकरण यात्रा शुरू होने से कम से कम 10 दिन पहले तक कराया जा सकता है। यात्रियों को अपने-अपने राज्यों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मेडिकल जांच और टीकाकरण पूरा करने की सलाह दी गई है, ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। एनआरआई यात्रियों को भी सुविधा देते हुए कहा गया है कि वे भारत या विदेश में किसी सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सक से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसकी प्रति निर्धारित समय में संबंधित राज्य हज समिति को जमा करना अनिवार्य होगा। वहीं टीकाकरण भी वे अपने खर्च पर भारत या विदेश में करवा सकते हैं। हज कमेटी ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे समयसीमा का पालन करें और सभी औपचारिकताएं पूरी कर समय पर हज यात्रा की तैयारी सुनिश्चित करें।

महू में 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पर विशाल समागम, तैयारियां तेज

इंदौर/महू। इंदौर जिले के डॉ. अंबेडकर नगर महू में इस वर्ष भी 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। डॉ. भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर विशाल समागम आयोजित होगा, जिसमें देशभर से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। जयंती उत्सव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने महू पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी इंतजामों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं तय समय-सीमा में पूरी की जाएं।

19 मार्च से शुरू होगा हिंदू नव वर्ष 72 साल बाद बना दुर्लभ संयोग

अमावस्या और चैत्र नवरात्र एक साथ होंगे प्रारंभ, शहर के मंदिरों में तैयारियां तेज

इंदौर। शक्ति की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र इस वर्ष 19 मार्च से विशेष संयोग के साथ प्रारंभ हो रहा है। इसी दिन गुड़ी पड़वा के साथ हिंदू नववर्ष (रौद्र नाम संवत्सर) का भी शुभारंभ होगा। खास बात यह है कि इस बार अमावस्या और नवरात्र का आरंभ एक ही दिन पड़ रहा है, जो करीब 72 वर्षों बाद बन रहा दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मंदिरों में साफ-सफाई, रंग-रोगन और आकर्षक विद्युत सजावट का कार्य जोरों पर चल रहा है। बिजासन माता मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, कालिका धाम खजराना, वैष्णोधाम मंदिर, गीताभवन सहित अन्य मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और घटस्थापना की जाएगी। ज्योतिषाचार्य पं. रामचंद्र शर्मा वैदिक के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र का आरंभ होता है, लेकिन इस बार अमावस्या के साथ इसका प्रारंभ होना अत्यंत शुभ और दुर्लभ है। इस नवसंवत्सर में राजा गुरु और मंत्री मंगल रहेंगे, जो धार्मिक दृष्टि से विशेष फलदायी माने जा रहे हैं।

घटस्थापना के शुभ मुहूर्त- पंचांग के अनुसार 19 मार्च को घटस्थापना के लिए सुबह 6:54 से 8:06 बजे तक शुभ समय रहेगा। इसके अलावा दोपहर 12:11 से 12:58 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकेगी।

8 दिन का रहेगा नवरात्र- इस वर्ष अष्टमी और नवमी एक ही दिन 26 मार्च को पड़ने से नवरात्र 8 दिन के रहेंगे। पहले दिन शुक्ल योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जिनमें माता रानी की पूजा-अर्चना विशेष फलदायी मानी गई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्र में नई शुरुआत, खरीदारी, निवेश और शुभ कार्य करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस विशेष संयोग के चलते श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने की संभावना है।

1 अप्रैल से खुलेंगे सरकारी स्कूल, घर-घर जाकर छात्रों को लाएंगे शिक्षक

इंदौर। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होने जा रही है। इस बार सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की घटती संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विशेष रणनीति बनाई है। इसके तहत शिक्षक अब घर-घर जाकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे। विभाग ने स्कूल प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि सत्र शुरू होने से पहले सभी स्कूलों में रंगाई-पुताई, साफ-सफाई और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त कर ली जाएं, ताकि बच्चों को बेहतर माहौल मिल सके।

ड्रॉपआउट पर खास फोकस- हर साल बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, खासकर कक्षा 5वीं से 6वीं और 8वीं से 9वीं में प्रवेश के दौरान। ऐसे छात्रों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए इस बार सत्र की शुरुआत से ही अभियान चलाया जाएगा। शिक्षकों को 'वार्डन' की जिम्मेदारी देते हुए कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान कर उन्हें फिर से स्कूल से जोड़ें।

घर-घर जाकर करेंगे संपर्क- अप्रैल महीने में विद्यार्थियों का चिन्हांकन और नामांकन पूरा किया जाएगा। इसके बाद जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे, उनके घर जाकर शिक्षक अभिभावकों से संपर्क करेंगे और बच्चों को नियमित पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे।

शुरुआत में ही किताबें उपलब्ध- शिक्षा विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि नए सत्र के पहले चरण में ही छात्रों को पाठ्यपुस्तकों का वितरण कर दिया जाए, ताकि पढ़ाई बिना किसी देरी के शुरू हो सके।

शिक्षकों पर बढ़ा बोझ- हालांकि इस योजना के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। सरकारी स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की कमी है, ऊपर से उन्हें चुनाव और अन्य शासकीय कार्यों में भी लगाया जाता है। ऐसे में बच्चों को घर-घर जाकर स्कूल लाने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, जिससे इस अभियान की सफलता पर सवाल उठ रहे हैं।

उम्मीद और चुनौती दोनों- शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि इस पहल से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी और ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी। वहीं, जमीनी स्तर पर संसाधनों और स्टाफ की कमी इस योजना की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है।

इंदौर में बड़ी सर्जरी: महिला के शरीर से 6.3 किलो का ओवरी ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला

इंदौर। इंदौर के इंडेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने जटिल सर्जरी कर 36 वर्षीय महिला के शरीर से 6.3 किलो का विशाल ओवरी ट्यूमर निकालकर उसे नई जिंदगी दी। करीब तीन घंटे चली इस सर्जरी में ट्यूमर को बिना फटे सुरक्षित बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसमें डॉक्टरों को सफलता मिली। डॉक्टरों के अनुसार ट्यूमर का आकार लगभग 27 सेंटीमीटर तक पहुंच चुका था, जिससे मरीज के पेट में सूजन, लगातार दर्द और आंतों पर दबाव की समस्या हो रही थी। महिला पिछले कई महीनों से असामान्य मासिक धर्म और बढ़ती तकलीफ से जूझ रही थी, लेकिन हाल ही में उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि मरीज के गर्भाशय में 6 सेमी और 3.1 सेमी के दो फाइब्रॉयड भी मौजूद थे। सर्जरी के दौरान विशेष सावधानी बरती गई, क्योंकि ट्यूमर के

फटने पर संक्रमण और अन्य जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता था। सफल ऑपरेशन के बाद निकाले गए ट्यूमर को जांच के लिए भेजा गया है, ताकि इसके प्रकार और संभावित जोखिम का पता लगाया जा सके। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है और उसे निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि ओवरी ट्यूमर महिलाओं में होने वाली गंभीर समस्या हो सकती है, जो धीरे-धीरे बड़ा आकार ले लेती है। इसके लक्षणों में पेट दर्द, सूजन, असामान्य मासिक धर्म और कमजोरी शामिल हैं। समय पर जांच और इलाज से गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है।

अनन्या पांडे ने शेयर की अपने रिलेशनशिप की मुश्किलें

खुद को हमेशा कमतर समझा

अनन्या पांडे ने हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में पुराने रिलेशनशिप उससे जुड़ी उम्मीदें और अपने निजी जीवन के बारे में काफी कुछ बताया। एक्ट्रेस ने खुद के जीवन जीने के तरीकों में बदलाव की बात भी कही।

एक्ट्रेस ने रिश्तों से मिला दुख किया शेयर

अनन्या पांडे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ काफी समय बिताती हैं। हार्पर बाजार इंडिया को दिए अपने इंटरव्यू में अनन्या ने अपने अतीत और निजी जीवन के नजरिए के बारे में काफी कुछ शेयर किया। एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे अकेले रहने में काफी परेशानी होती है। वह हर वक्त परिवार और दोस्तों से घिरे रहना पसंद करती हैं। मगर कुछ समय बाद मुझे अकेले रहने का महात्व समझ आया। ऐसा करने से मैंने अपने जीवन में एक बदलाव महसूस किया। मुझे रिश्तों पर दोबारा सोचने का समय मिला।'

खुद को हमेशा कमतर समझा

एक्ट्रेस ने अपनी बातचीत में आगे बताया कि उनके पिछले रिश्ते से उन्होंने काफी सबक लिए। इस रिश्ते ने उनके आत्म-सम्मान पर भी काफी प्रभाव डाला। अकेलेपन के पहले जब वो रिश्ते में थी उन्होंने खुद को हमेशा कमतर समझा। वह हमेशा यह चाहती थी कि सामने वाले की अहमियत उनसे ज्यादा हो। जिस वजह से वह उस व्यक्ति के हिसाब से खुद को बदल लेती थीं। मगर अब वो अपने अंदर एक अलग चेंज लेकर आई हैं।

जल्द रिलीज होगी अनन्या की फिल्म

एक्ट्रेस की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा..' हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म में उनके साथ कार्तिक आर्यन भी नजर आए थे। अब अनन्या की दूसरी फिल्म धर्मा प्रोडक्शन की रोमांटिक ड्रामा 'चांद मेरा दिल' रिलीज होगी। 8 मई, 2026 को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

चंबल की लोककथाओं पर बेस्ड होगी 'शक्ति शालिनी'

यशराज फिल्म्स की 'सेयारा' से चर्चा में आई अनीत पड्डा और 'मर्दानी 2' व 'होमबाउंड' से पहचान बना चुके विशाल जेठवा तेजी से बड़े बैनर्स की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। अब ये दोनों कलाकार पहली बार मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स में एक साथ नजर आने वाले हैं। दिनेश विजन और अमर कौशिक के सुपरहिट यूनिवर्स में अगली पेशकश 'शक्ति शालिनी' होगी। सूत्रों के मुताबिक, यह फिल्म अनीत को एक महिला-प्रधान सुपरनैचुरल किरदार में पेश करेगी, जबकि विशाल उनके लव इंटरेस्ट की भूमिका निभाएंगे। हालांकि यह रिश्ता सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं रहेगा, चल्कि कहानी को नैतिक गहराई और भावनात्मक आधार भी देगा।

कियारा के हटने के बाद अनीत हुई कास्ट- अक्टूबर 2024 तक इस प्रोजेक्ट से कियारा आडवाणी का नाम जुड़ा था, लेकिन अब फिल्म अनीत के खाते में है। मार्च 2026 से शूटिंग शुरू होने की संभावना है। 'शक्ति शालिनी' को 'मुंज्या' फेम आदित्य सरपोतदार डायरेक्ट करेंगे।

'कल्कि 2' में दीपिका की जगह नजर आएंगी साई पल्लवी

साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 AD' साल 2024 में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म के निर्देशक नाग अश्विन ने इसके सीक्वल पर काम भी शुरू कर दिया है। इसका संकेत अमिताभ बच्चन ने अपने एक विडियो में दिया था। पिछले साल 2025 में खबर आई थी कि दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2' का हिस्सा नहीं होंगी। इसके बाद से निर्माता नई एक्ट्रेस की तलाश में थे। अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक... 'फिल्म के लिए साई पल्लवी को फाइनल कर लिया गया है। वह सीक्वल में दीपिका की जगह नजर आएंगी। कास्ट के एक सदस्य ने पुष्टि करते हुए कहा कि दीपिका के बाहर होने के बाद इस किरदार को खत्म करने का सवाल ही नहीं था, इसलिए साई पल्लवी को चुना गया। एक सूत्र के अनुसार... 'दीपिका ने सीक्वल के लिए पहली फिल्म से लगभग 35 प्रतिशत ज्यादा फीस की मांग की थी।

नवोदय विद्यालय प्रवेश नीति पर सवाल: EWS छात्रों को मौका न मिलने पर हाईकोर्ट सख्त

भोपाल। जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6वीं (सत्र 2026-27) की प्रवेश प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को अवसर न दिए जाने का मामला अब न्यायालय पहुंच गया है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए केंद्र सरकार, नवोदय विद्यालय समिति सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब तलब किया है। यह याचिका नाबालिग छात्रा नव्या तिवारी की ओर से उनके अभिभावक धीरज तिवारी द्वारा दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण और वंचित वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ऐसे में ईडब्ल्यूएस वर्ग को प्रवेश से बाहर रखना इस उद्देश्य के विपरीत है। याचिका के अनुसार, नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों, बालिकाओं और दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जिससे यह वर्ग पूरी तरह वंचित रह जाता है। देशभर में 450 से अधिक नवोदय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें लगभग 2.9 लाख छात्र अध्ययनरत हैं। याचिका में उल्लेख किया गया है कि 103वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया, , जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए शिक्षा संस्थानों में 10% तक आरक्षण का प्रावधान है। इसके बावजूद नवोदय विद्यालयों की प्रवेश नीति में इसे लागू नहीं किया गया, जिसे संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी बताया गया है। मामले में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को प्रवेश का अवसर मिलता है, जबकि उसी मंत्रालय के अधीन संचालित नवोदय विद्यालयों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसे याचिका में भेदभावपूर्ण और असंगत बताया गया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए। याचिका में अथर्व चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश एंड अदर्स मामले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस छात्रों को अवसर न मिलने को गंभीर विषय माना गया था। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस का हमला: MSP बोनस, खरीदी और कर्ज नीति पर सरकार घिरी

0% ब्याज का दावा, 16-20% की मार - किसान कर्ज जाल में फंस रहा

भोपाल। कुणाल चौधरी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पूर्व विधायक, ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों के मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां किसानों के हित में नहीं, बल्कि उनके शोषण का माध्यम बन चुकी हैं। चौधरी ने कहा कि एमएसपी पर खरीदी में गड़बड़ी हो रही है और सरकार द्वारा घोषित 575 प्रति क्विंटल बोनस के बजाय मात्र 40 बढ़ाकर किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि पूरा बोनस तुरंत लागू किया जाए। खरीदी तिथि में बदलाव को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। पहले 16 मार्च से शुरू होने वाली गेहूं खरीदी को 1 अप्रैल तक टालने को किसान विरोधी बताते हुए उन्होंने खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की, ताकि किसानों को पर्याप्त समय मिल सके। कांग्रेस नेता ने कृषि कल्याण वर्ष पर सवाल उठाते हुए इसे किसान शोषण वर्ष करार

दिया और आरोप लगाया कि सरकार कर्ज और ब्याज के जरिए किसानों को जाल में फंसा रही है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के नाम पर नीतियां बनाकर उन्हें लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा। अंतरराष्ट्रीय ट्रेड डील और वैश्विक परिस्थितियों पर चिंता जताते हुए चौधरी ने कहा कि विदेशी कृषि उत्पादों के आयात, कच्चे तेल की कीमतों में संभावित वृद्धि और उर्वरक आपूर्ति पर असर से किसानों की लागत बढ़ सकती है। उन्होंने गेल (इंडिया) लिमिटेड की गैस आपूर्ति प्रभावित होने से खाद उत्पादन पर असर पड़ने का भी मुद्दा उठाया, जिससे आगामी खरीफ सीजन में संकट गहरा सकता है। चौधरी ने सरकार पर किसानों के साथ धोखा, एमएसपी में अनियमितता और कम बोनस देकर ठगने के आरोप लगाए। उन्होंने प्रमुख मांगों में 575 बोनस लागू करने, समयबद्ध खरीदी, कर्ज राहत और किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात रखी। अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया, तो कांग्रेस प्रदेशभर में आंदोलन करेगी। इस दौरान विवेक त्रिपाठी, अवनीश बुंदेला और राहुल राज सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

खतरनाक साबित हो सकता था आतंकियों द्वारा सोलर-बेस्ड कैमरे लगाना

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली-एनसीआर में आतंकियों द्वारा सोलर-बेस्ड कैमरे लगाने के मामले ने सुरक्षा विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली-एनसीआर के संवेदनशील इलाकों में संदिग्ध सोलर-बेस्ड कैमरों की मौजूदगी को लेकर कई बार अलर्ट जारी कर चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पारंपरिक जासूसी से कहीं अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि सोलर पैनल होने के कारण इन कैमरों को बाहरी बिजली या बैटरी बदलने की जरूरत नहीं होती है। यह एक बार लगाओ और भूल जाओ जैसी तकनीक पर काम करता है, जिससे जासूसी करने वाले को लंबे समय तक संवेदनशील डाटा मिलते रहता है। स्पेशल सेल के एक अधिकारी का कहना है कि ये कैमरे अक्सर एन्क्रिप्टेड क्लाउड या विदेशी सर्वरों से जुड़े होते हैं। सीमा पार बैठे आका दिल्ली की सड़कों, वीआइपी मूवमेंट और सुरक्षा चौकियों को लाइव देख सकते हैं। ये कैमरे छोटे होते हैं और अक्सर पेड़ की टहनियों, स्ट्रीट लाइटों या ऊंची इमारतों के कोनों में छिपा दिए जाते हैं। सामान्य व्यक्ति इन्हें साधारण वाई-फाई कैमरा समझकर नजरअंदाज कर देता है। इस तरह के कैमरे लगाने का मुख्य उद्देश्य किसी बड़े हमले से पहले इलाके की डिजिटल रेकी करने के जैसा होता है, ताकि वहां की सारी गतिविधियों के पैटर्न को ठीक से समझा जा सके। अगर देश की सुरक्षा

एजेंसियां और स्थानीय पुलिस द्वारा समय रहते इस तरह के कैमरों को नहीं हटाया गया, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां यह मानती है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई दस कदम आगे का सोचती है भले ही आईएसआई की हर हरकत का पता लगा भारतीय एजेंसियां उसे ध्वस्त कर देती है। इस तरह के कैमरे लगाने के पीछे आईएसआई का मकसद यह होता है कि भारत में वीआइपी मूवमेंट का पता लगाया जाए, सुरक्षा काफिले के समय और रूट की सटीक जानकारी प्राप्त की जाए। वहीं, भीड़भाड़ वाले इलाके, मेट्रो स्टेशन और बाजारों में सुरक्षा खामियों का पता लगाया जाए। कैमरों के जरिए प्राप्त जानकारी का उपयोग ड्रोन हमलों के लिए किया जा सकता है।

दुश्मन को हमारे घर के अंदर झांकने का मौका दे रही: स्पेशल सेल के एक अधिकारी का कहना है कि सोलर बेस्ड कैमरा साधारण कैमरा नहीं होता है, इसे ''डिजिटल आई'' के रूप में माना जा सकता है जो दुश्मन को हमारे घर के अंदर झांकने का मौका दे रही है। इसलिए अगर यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार आतंकियों के बयान में अगर दिल्ली-एनसीआर में संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले जगहों पर सोलर कैमरे लगाने की जानकारी मिली है तो पूरे एनसीआर की पुलिस को ''इलेक्ट्रानिक ऑडिट'' करने की सख्त आवश्यकता है। पुलिस को सभी निजी और संदिग्ध कैमरों की जांच करनी चाहिए। क्योंकि पहली बार देश में इस तरह के बेहद खतरनाक मंसूबे वाला मामला सामने आया है।

इसे समझने की जरूरत: यह बहुत ही गंभीर मामला है, जिससे समय रहते सचेत होने की आवश्यकता है। हो सकता है सीमा पार बैठे आका भविष्य में इसको लेकर कोई खतरनाक प्लान कर रहा हो। इसे समझने की जरूरत है। पुलिस को संवेदनशील क्षेत्रों में संदिग्ध फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करने के लिए आरएफ (रेडियो फ्रिक्वेंसी) स्कैनर्स का उपयोग बढ़ाने की जरूरत है। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सलाह दी है कि यदि वे अपने आसपास कोई अनजान उपकरण या छोटा सोलर पैनल देखें, तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें।

किसान का गोबर गैस प्लांट बना प्रेरणास्त्रोत, हर रोज बनती है 2 केजी गैस; संकट के बीच खूब आ रहा काम

बाहरी दिल्ली, एजेंसी। रसोई गैस की किल्लत को लेकर एक ओर आम से लेकर खास सब चिंतित व परेशान हैं, लेकिन दरियापुर गांव के किसान सत्यवान सहरावत बेफिक्र हैं। गैस सिलिंडर को लेकर उन्हें न तो इधर-उधर की दौड़-धूप की चिंता और न ही ईंधन के दूसरे विकल्पों के लिए आपाधापी। इस बेफिक्री का कारण, उनके खेत में लगा गोबर गैस प्लांट है। लोग रसोई गैस को लेकर आपाधापी में हैं, वही सत्यवान अपने प्लांट से प्रतिदिन दो किलो गैस पैदा करते हैं। रसोई से लेकर 20 पशुओं का खाना तक गैस पर पकता है। रसोई गैस संकट के बीच बवाना क्षेत्र के दरियापुर गांव के प्रगतिशील किसान सत्यवान सहरावत का गोबर गैस प्लांट ऊर्जा के प्राकृतिक तौर-तरीके अपनाने के संदेश के साथ-साथ नई दिशा भी दिखा रहा है। सत्यवान ने लगभग आठ साल पहले 65 हजार रुपये की लागत से गोबर गैस प्लांट लगवाया था। तभी से नियमित रूप से प्लांट चल रहा है। बायो गैस प्लांट से पैदा गैस से प्रतिदिन रसोई के दैनिक कार्यों के अलावा पशुओं के लिए हर रोज 30-40 किलोग्राम तक दलिया पकता है। इसी गैस से 25-30 श्रमिकों का खाना भी तैयार किया जाता है। सत्यवान ने बताया कि प्लांट की क्षमता 10 घन मीटर है और यह 40 गज जमीन पर लगा है। प्लांट में प्रतिदिन लगभग दो सौ किलोग्राम खाद डाला जाता है, इससे दो किलोग्राम

गैस पैदा होती है। उन्होंने बताया कि आठ साल पहले उनके साथ-साथ कई लोगों ने गोबर गैस प्लांट लगवाया था, लेकिन अलग-अलग कारणों से अधिकांश लोगों का प्लांट बंद हो चुका है। सत्यवान ने सुझाव दिया कि बायो गैस प्लांट को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सब्सिडी देने पर विचार किया जाना चाहिए। गोबर गैस प्लांट गैस के साथ-साथ प्राकृतिक खाद भी देता है। सत्यवान सहरावत ने बताया कि वे प्रतिदिन लगभग दो सौ किलोग्राम गोबर प्लांट में डालते हैं और लगभग इतना ही प्राकृतिक खाद (सलरी) प्राप्त कर लेते हैं। यह खाद किसानों के लिए इसलिए और उपयोगी है कि प्लांट में डालने के बाद गोबर से हानिकारक मीथेन व कार्बन डाइआक्साइड गैस निकल जाती हैं। इन हानिकारक गैस के निकल जाने के बाद यह खाद फसल के लिए बेहद लाभदायी है। इस खाद के इस्तेमाल से खेत में खतपतवार भी नहीं पनप पाती है।

गैस सिलिंडर की भारी किल्लत, घंटों लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं लोग; कालाबाजारी को लेकर पुलिस सतर्क

पश्चिमी दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली के द्वारका उपनगर और उसके शहरी सेक्टरों में एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति जहां

सामान्य बनी हुई है, वहीं नजफगढ़ के गांव के इलाकों में रसोई गैस की किल्लत से उपभोक्ता परेशान हैं। सोमवार को गैस सिलिंडर लेने के लिए लोगों को सुबह से ही एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार के बाद भी सिलिंडर नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उपभोक्ताओं को सिलिंडर लेने के लिए पहले एजेंसी के दफ्तर में पर्ची बनवाने और फिर गोदाम तक जाने के लिए कहा जाता है। कई बार दफ्तर से गोदाम और गोदाम से वापस दफ्तर भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया में लोगों का पूरा दिन बीत जाता है और घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है। घर के पुरुष तो काम पर चले जा रहे हैं पर घर की महिलाओं और बुजुर्गों को सिलिंडर के लिए कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। इस अनियमित आपूर्ति के कारण उनकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो रही है। कई घरों में मजबूरी में इंडक्शन चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है। उनका कहना है कि देहात क्षेत्र में गैस की होम डिलीवरी भी नियमित नहीं हो रही, जिससे समस्या और बढ़ गई है। उधर, द्वारका के शहरी सेक्टरों में गैस की आपूर्ति सामान्य बताई जा रही है। यहां ज्यादातर सोसायटी में पीएनजी के पाइप लाइन बिछे हुए हैं। जो कुछ कॉलोनी और गांव हैं, वहां के उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी भी समय पर मिल रही है। इधर एलपीजी सिलिंडर की किल्लत के बीच संभावित कालाबाजारी को लेकर पुलिस भी सतर्क है। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि जिले में एलपीजी सिलिंडर की कालाबाजारी पर नजर रखी जा रही है। अब तक इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसएफआई दिल्ली का ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन

नई दिल्ली, एजेंसी। स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआइ) दिल्ली ने प्रस्तावित ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन आफ राइट्स) संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में सोमवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से इस विधेयक को तुरंत वापस लेने की मांग की और ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ एकजुटता जताई। उनका कहना था कि प्रस्तावित संशोधन ट्रांसजेंडर लोगों के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी सुरक्षा को कमजोर करता है। प्रदर्शन के बाद एसएफआइ दिल्ली के प्रतिनिधिमंडल प्रत्यय, इप्सिता और उर्सुला ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक नालसा बनाम भारत सरकार (2014) फैसले की भावना के खिलाफ है, जिसमें लैंगिक पहचान के आत्मनिर्णय के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया था। एसएफआइ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित संशोधन में आत्म-पहचान के अधिकार को खत्म कर लैंगिक पहचान तय करने का अधिकार सरकारी मेडिकल बोर्ड को देने की बात कही गई है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा और निजता के अधिकार का उल्लंघन है। संगठन ने मांग की कि विधेयक तुरंत वापस लिया जाए, आत्म-पहचान के सिद्धांत को बरकरार रखा जाए।

एप्पल कंपनी के नाम पर बेच रहे थे नकली एसेसरीज

4 को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में फर्जी सामान जब्त

इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग पर एप्पल कंपनी के नाम से नकली मोबाइल एसेसरीज बेचने वाले चार दुकान संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली लोगो, कवर और चार्जिंग एसेसरीज बरामद की हैं। एप्पल कंपनी के प्रतिनिधि विशाल जडेजा ने भंवरकुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि भोलाराम उस्ताद मार्ग स्थित कुछ दुकानों पर कंपनी के ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर नकली सामान असली बताकर बेचा जा रहा है। थाना प्रभारी राजकुमार यादव के निर्देशन में उप निरीक्षक धर्मवीर सिंह चौहान की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से चिन्हित दुकानों पर दबिश दी।कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है। पकड़ाए आरोपियों की पहचान संतोष रावत निवासी मनावर मूसाखेड़ी, ऋतिक वाधवानी निवासी राजा बाग कॉलोनी, निलेश गौतम और अविनाश निवासी सुदामा नगर के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से एप्पल के नकली लोगो वाले मोबाइल कवर, 25 से अधिक चार्जिंग केबल, एडेप्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया गया है। सभी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

यहां भी कार्रवाई

इसी प्रकार नकली सामान के खिलाफ एक अन्य कार्रवाई सेंट्रल कोतवाली पुलिस द्वारा की गई। पुलिस ने मोहन पिता ओमप्रकाश सिंधी को गिरफ्तार किया है, जो एक नामी कंपनी के रैपर का उपयोग कर नकली वाशिंग पाउडर बेच रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20 किलो से अधिक नकली पाउडर बरामद किया है। मामले में कॉपीराइट और जालसाजी की धाराओं में जांच की जा रही है।

महिला के बैग से उड़ाए डेढ़ लाख के जेवर, आटो चालक पर लगाया आरोप

इन्दौर। रानीपुरा बाजार में एक आटो रिक्शा में बैठी महिला के करीब डेढ़ लाख रुपए के जेवर गायब हो गए। मामले में महिला ने आटो चालक पर आरोप लगाया कि उसने अपनी बातों के जाल में उलझाया और बैग में रखे करीब डेढ़ लाख रुपये के सोने के जेवर व नगदी लेकर चंपत हो गया।

सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने अज्ञात रिक्शा चालक के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, केसर बाग रोड निवासी नीतू पति कार्तिकेय चौहान ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह 11 मार्च को अपनी बहन के साथ खरीदारी करने के लिए रानीपुरा बाजार आई थीं। उनके पास एक बैग था, जिसमें 18 सोने के मोती, एक सोने का मंगलसूत्र, दो अंगूठियां और 5 हजार रुपये नगद रखे हुए थे।फरियादी नीतू ने पुलिस को बताया कि शाम करीब 5 बजे उन्होंने घर जाने के लिए एक आटो रिक्शा को रोका और उसे केसर बाग रोड छोड़ने के लिए कहा। सफर के दौरान रिक्शा चालक ने उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया। इसी बीच मौका पाकर उसने शातिर तरीके से बैग चोरी कर लिया। जब महिला को बैग गायब होने का अहसास हुआ, तब तक आरोपी चालक वहां से भाग चुका था। सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने चोरी की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस अब रानीपुरा और केसर बाग रोड के बीच के सभी प्रमुख रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है, ताकि ऑटो रिक्शा के नंबर और चालक के हुलिए की पहचान की जा सके।

फल लेने रुके व्यक्ति का कार से बैग चोरी- उधर, अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सुदामा नगर स्थित सेठी गेट के पास एक व्यक्ति की कार से अज्ञात बदमाश ने बैग चुरा लिया। बैग में महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ नकदी भी रखी हुई थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार, वीआईपी परस्पर नगर निवासी चन्द्रमोहन सिंह पिता नाहरसिंह सोलंकी ने शिकायत दर्ज कराई है। चन्द्रमोहन सिंह अपनी कार से जा रहे थे, तभी सुदामा नगर के पास सेठी गेट के समीप वह फल खरीदने के लिए रुके थे। उन्होंने अपनी कार खड़ी की और फल लेने लगे। फल खरीदने के दौरान उनकी नजर अपनी कार से हटी और इसी का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाश ने कार के भीतर रखा ब्राउन रंग का बैग चोरी कर लिया। बैग में जरूरी दस्तावेज और नकदी रखी हुई थी। जब चन्द्रमोहन वापस कार के पास पहुंचे, तो उन्हें बैग गायब मिला। आसपास पूछताछ करने पर भी कोई सुराग नहीं लगा।

विक्रमादित्य विवि के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम और राज्यपाल

महाकाल की नगरी को सौगात, विकास को मिलेगी रफ्तार

उज्जैन. एजेंसी

महाकाल की नगरी उज्जैन को आज बड़ी सौगातें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने 77 करोड़ रु की लागत से बनने वाले 'गीता भवन' का भूमि-पूजन किया । इसके साथ ही सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए उज्जैन विकास प्राधिकरण की 662.46 करोड़ रु से तैयार होने वाली विभिन्न शहरी विकास योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। माना जा रहा है कि इससे उज्जैन के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने सम्राट विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर सम्राट 103 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, 74 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि और एक विद्यार्थी को डी-लिट की उपाधि प्रदान की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने 29.84 रुपए करोड़ की लागत वाले सिंहस्थ मेला कार्यालय का निर्माण कार्य का भूमि-पूजन भी किया। सिंहस्थ क्षेत्र में लगभग 35 किलोमीटर लंबी सीसी सड़कों का निर्माण, सीवर लाइन, जल आपूर्ति और स्थायी भूमिगत विद्युतीकरण के कार्यों की शुरुआत की गई है। इसके अलावा विक्रम नगर आरओबी का निर्माण किया जा रहा हैं, जिससे विक्रम उद्योगपुरी के लिए मक्सी एवं देवास से आने वाले यातायात में आसानी होगी।

सम्राट विक्रमादित्य विवि के दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।

सदन में नहीं चलेंगी तख्तियां और बैनर

स्पीकर ने पढ़ाया अनुशासन का पाठ, सांसदों का निलंबन वापस

नईदिल्ली. एजेंसी

लोकसभा के आठ सांसदों का निलंबन निरस्त हो गया है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से प्रस्ताव रखे जाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा सांसदों की तरफ से मतदान कराया। निलंबन रद्द किए जाने की सहमति बनने पर उन्होंने आठों सांसदों का नाम लेकर कहा कि सभी सांसदों का निलंबन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा रहा है। अब ये सभी सांसद संसद के बजट सत्र में हिस्सा ले सकेंगे। इस फैसले के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर तख्तियां, बैनर और एआई जनित तस्वीरों के इस्तेमाल की सख्त मनाही है। सभी सांसदों को इसका ध्यान रखना चाहिए।

इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि सरकार या सत्ताधारी खेमा किसी भी सांसद को सदन की कार्यवाही से जानबूझकर बाहर निकालना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। निलंबन की कार्रवाई और सांसदों को राहत दिए जाने पर चर्चा के दौरान महाराष्ट्र से निर्वाचित महिला सांसद सुप्रिया सुले ने असहमति को दबाए जाने को लेकर चिंता जाहिर की। गौरतलब है कि विगत तीन फरवरी को संसद में हंगामे के दौरान मर्यादा तार-तार हुई थी। नारेबाजी और हंगामा करने वाले कुछ सांसदों ने स्पीकर के आसन तरफ दो बार कागज फेंके थे। इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए सांसदों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया था।

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर ओडिशा कांग्रेस का एक्शन, तीन विधायक सस्पेंड

भुवनेश्वर। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के तीन विधायकों को महंगी पड़ गई। पार्टी ने कड़ा कदम उठाते हुए विधायक सोफिया फिरदौस, रमेश जेना और दाशरथी गमांग को निलंबित कर दिया है। वहीं कटक नगर सभा की सभानेत्री गिरिबाला बेहरा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद दास ने बताया कि तीनों विधायकों पर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप है। उन्होंने कहा कि इन तीनों को स्थायी रूप से निष्कासित करने के लिए अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी बिल पास

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता विधेयक पास हो गया है। यह कानून जबरदस्ती, लालच, धोखे या शादी के जरिए होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति शादी का झांसा देकर किसी का धर्म बदलवाता है, तो उसे 7 साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। यदि अपराध नाबालिग, महिला या एससी-एसटी के व्यक्ति के साथ होता है, तो जुर्माना 5 लाख होगा। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में भी 7 साल की जेल और 5 लाख जुर्माने का नियम है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, आरोप पत्र और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया

आपसी सहमति से लंबे समय तक शारीरिक संबंध रेप नहीं

प्रयागराज. एजेंसी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि दो वयस्क व्यक्ति आपसी सहमति से लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखते हैं, तो रिश्ते के टूटने या शादी का वादा पूरा न होने पर इसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाना चाहिए।

यह फैसला रामपुर जिले के निवासी अजय सैनी के खिलाफ दर्ज रेप के मामले में आया है। जस्टिस अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने आरोपी की याचिका पर सुनवाई के बाद रामपुर की निचली अदालत में लंबित आरोप पत्र और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। मामले के अनुसार, एक युवती ने वर्ष 2024 में अजय सैनी के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता का दावा था कि वर्ष 2019 में आरोपी ने नौकरी दिलाने के बहाने उसे मुरादाबाद ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी का झांसा देकर चार साल तक उसका शारीरिक शोषण जारी रखा। जब उसे पता चला कि आरोपी कहीं और शादी करने जा रहा है, तब उसने पुलिस में शिकायत की।

कभी न मिटने वाला सामाजिक कलंक : कोर्ट ने आगे कहा, 'हर असफल या टूटे रिश्ते को दुष्कर्म का मामला बना देना न केवल इस अपराध की गंभीरता को कम करता है, बल्कि आरोपी पर कभी न मिटने वाला सामाजिक कलंक भी लगा देता है। कानून की प्रक्रिया का इस तरह दुरुपयोग रोका जाना चाहिए।' यह फैसला ऐसे मामलों में नजीर के तौर पर देखा जा रहा है, जहां शादी का वादा टूटने पर बाद में बलात्कार का आरोप लगाया जाता है।

पीड़िता के बयान में विरोधाभास

कोर्ट ने पीड़िता के बयानों में पाए गए कई विरोधाभासों पर गौर किया। एफआईआर में जहां होटल के कमरे का जिक्र था, वहीं बाद के बयानों में रेस्टोरेंट में नशीला पदार्थ दिए जाने की बात कही गई। कोर्ट ने यह भी देखा कि पीड़िता शिक्षित है और चार वर्षों तक किसी भी मंच पर इस घटना की शिकायत नहीं की। जस्टिस सक्सेना ने अपने फैसले में कहा कि दोनों पक्षों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे और लंबे समय तक चले। रिश्ते के टूटने के बाद इसे आपराधिक रंग देना उचित नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराध की धाराओं का इस्तेमाल केवल वास्तविक यौन हिंसा, जबरदस्ती या धोखाधड़ी के स्पष्ट मामलों में ही होना चाहिए।

अहमदाबाद को मिलेगी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी कार्यकारी बोर्ड ने नाम की सिफारिश की

नई दिल्लीः राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के प्रस्तावित मेजबान के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश की जिससे भारत में दो दशक के बाद इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की वापसी का रास्ता साफ हो रहा है। मेजबानी पर अंतिम फैसला 26 नवंबर को ग्लास्गो में राष्ट्रमंडल खेल की आम सभा की बैठक में लिया जाएगा जो अब सिर्फ औपचारिकता नजर आता है। इससे पहले सिफारिश को राष्ट्रमंडल खेल के सभी सदस्यों के पास भेजा जाएगा।

भारत ने 2010 में आखिरी बार खेलों की मेजबानी दिल्ली में की थी। खेलों की मेजबानी का अधिकार प्राप्त करना भारत के लिए 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लक्ष्य में भी महत्वपूर्ण होगा। ओलंपिक खेलों के मेजबान के रूप में अहमदाबाद प्रस्तावित है। भारत को नाइजीरिया से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था लेकिन राष्ट्रमंडल खेल ने भविष्य के खेलों के लिए इस अफ्रीकी देश की मेजबानी की महत्वाकांक्षाओं को 'समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक रणनीति विकसित करने' का निर्णय लिया है, जिसमें 2034 खेलों की मेजबानी पर विचार भी शामिल है। खेलों की मेजबानी का अधिकार प्राप्त करना भारत के लिए 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लक्ष्य में भी महत्वपूर्ण होगा। ओलंपिक खेलों के मेजबान के रूप में अहमदाबाद प्रस्तावित है। भारत को नाइजीरिया से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था लेकिन राष्ट्रमंडल खेल ने भविष्य के खेलों के लिए इस अफ्रीकी देश की मेजबानी की महत्वाकांक्षाओं को 'समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक रणनीति विकसित करने' का निर्णय लिया है, जिसमें 2034 खेलों की मेजबानी पर विचार भी शामिल है। यह सिफारिश राष्ट्रमंडल खेल मूल्यांकन समिति की देखरेख में चली प्रक्रिया के बाद की गई है। इसमें 'तकनीकी वितरण, खिलाड़ियों के अनुभव, बुनियादी ढांचे, संचालन और राष्ट्रमंडल खेल मूल्यों के साथ संरेखण' के आधार पर उम्मीदवार शहरों का मूल्यांकन किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया, 'भारत के अहमदाबाद और नाइजीरिया के अबुजा दोनों ने आकर्षक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जो राष्ट्रमंडल खेल आंदोलन की महत्वाकांक्षा और क्षमता को दर्शाते हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'भारतीय खेलों के लिए एक बड़ा क्षण !...यह निर्णय वैश्विक खेलों में भारत के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा संभव हुआ है।